अस्थाई कोल लिंकेज मंजूर

शीघ्र जारी हो अधिसूचना : नीतीश

जागरण ब्यूरो, पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बरौनी थर्मल पावर प्लांट के लिए अस्थाई कोल लिंकेज के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी दे दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर इसके लिए तत्काल अधिसूचना जारी कर देने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव ने भी केंद्रीय ऊर्जा सचिव को सरकार की इस रजामंदी से अवगत करा दिया है।

प्रधानमंत्री डा. सिंह ने श्री कुमार को 19 जुलाई के लिखे अपने पत्र में कोयला मंत्रालय के इस प्रस्ताव से अवगत कराया था। प्रस्ताव के तहत बरौनी इकाई को उरमापहाड़ी कोल ब्लाक दिया जाएगा और इस खदान से खनन शुरू होने तक टैपरिंग(अस्थाई) कोल लिंकेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में डा.सिंह को बताया है कि उन्हें यह प्रस्ताव मंजूर है और इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्रीय ऊर्जा सचिव को अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में सूबे में बरौनी थर्मल पावर प्लांट सरकारी क्षेत्र में अकेला प्रोजेक्ट है जिससे 500 मेगावाट बिजली मिलेगी। हम लोग प्रयासरत हैं कि यह प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समय जनवरी-जुलाई, 2014 तक पूरा हो जाए। इस कारण यह आवश्यक है कि 'टैपरिंग कोल लिंकेज' के तहत किसी कार्यरत कोयले की खान से कोयले की सप्लाई 2014 में आरंभ कर दी जाए। यह 2018 तक जारी रहे जब तक कि ■ शेष पृष्ठ 21 पर

बोले नीतीश

- 31 अगस्त तक मिल जाए कोयला कंपनी का आश्वासन पत्र
- मुख्य सचिव ने केंद्रीय ऊर्जा सचिव को सहमति से अवगत कराया
- बरौनी थर्मल पावर प्लांट के लिए हुई है यह व्यवस्था

प्रथम पृष्ठ का शेष

अस्थाई कोल लिंकेज मंजूर

उरमापहाड़ी कोल ब्लाक से उत्पादन नहीं शुरू हो जाए। इसके बाद भी तीन साल तक के लिए हमें 'टैपरिंग सप्लाई' दी जाए। चूंकि बरौनी थर्मल पावर प्लांट के लिए 'इंवायरेंमेंट क्लीयरेंस' 31 जनवरी, 2013 तक प्राप्त कर लेना है, ऐसे में 'टैपरिंग लिंकेज' के संबंध में तुरंत अधिसूचना जारी करें। साथ कोयला कंपनी इस संबंध में आश्वासन पत्र(एलओए) 31 अगस्त तक जारी कर दे। सूबे के लिए बरौनी इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि कोयला, पर्यावरण एवं ऊर्जा मंत्रालयों से इसके निर्माण में हर संभव सहयोग दिलाएं।

मुख्य सचिव नवीन कुमार ने केंद्रीय ऊर्जा सचिव एसके श्रीवास्तव को सरकारी की सहमति से अवगत कराते हुए कहा है कि झारखंड स्थित उरमापहाड़ी खदान से 2018 में उत्पादन की उम्मीद है। इसके लिए अक्टूबर, 2012 तक 'माइन डेवलपर एंड आपरेटर'(एमडीओ) चुने जाएंगे और उन्हें मार्च, 2013 तक लाइसेंस निर्गत होगा। प्रस्तावित टैपरिंग कोल लिंकेज की अवधि इन औपचारिकताओं में लगे समय को ध्यान में रखकर ही तय की जाए। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड(बीएसईबी) ने 27 जून, 2006 को ही इस प्रोजेक्ट के वास्ते कोल लिंकेज के लिए आवश्यक फीस के साथ आवेदन दिया था। इस आवेदन को प्रस्तावित टैपरिंग कोल लिंकेज के लिए माना जाए।